दैनिक जागरण

आत्ममुग्धता पतन का पहला पड़ाव है

न्याय का तकाजा

वीवीआइपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी यही बताती है कि इस घोटाले की जड़ें कहीं गहरे तक फैली हुई थीं। फिलहाल यह कहना कठिन है कि हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच-पड़ताल कब पूरी होगी, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि विशिष्ट व्यक्तियों के लिए हेलीकॉप्टर खरीद में घोटाला हुआ था। हैरानी यह है कि राहुल गांधी राफेल सौदे को लेकर तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर घोटाले पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे हैं। वह बीते सात-आठ माह से राफेल सौदे को तूल देने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक यह नहीं स्पष्ट कर सके हैं कि इन लड़ाकू विमानों की खरीद में किस तरह की गड़बड़ी हुई और कैसे देश का पैसा इधर-उधर हुआ? उनके पास ले-देकर यही कहने को है कि मोदी जी ने अनिल अंबानी की जेब में तीस हजार करोड़ रुपये डाल दिए। वह इस आरोप के पक्ष में भी कोई सुबूत नहीं दे पा रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि वह राफेल सौदे पर बिना किसी प्रमाण चौकीदार चोर है का नारा इसीलिए जोर-शोर से उछालने में लगे हुए हैं ताकि देश का ध्यान हेलीकॉप्टर घोटाले समेत उन अन्य अनेक घोटालों की ओर न जाए जो मनमोहन सरकार के समय में हुए थे। अगर इस तरह की नारेबाजी सही है तो फिर हेलीकॉप्टर घोटाले में किसे चोर कहा जाना चाहिए?

मनमोहन सरकार के समय के न जाने कितने घोटाले हैं जिनकी जांच-पड़ताल यह बताती है कि उस दौरान सार्वजनिक कोष के धन को जमकर लूटा गया। कुछ घोटाले तो ऐसे हैं जिनमें खुद कांग्रेस अध्यक्ष और उनके परिजन जांच के घेरे में हैं। आखिर यह एक तथ्य है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को अनुचित तरीके से अपने स्वामित्व वाले ट्रस्ट के हवाले करने के मामले में राहुल गांधी जमानत पर हैं। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के पति राबर्ट वाड्रा जमीनों के संदिग्ध सौदों के कारण प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कुछ ऐसे ही चक्कर कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम को काटने पड़ रहे हैं। न्याय का तकाजा यह कहता है कि जब तक आरोप साबित न हो जाएं तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन न्याय का यह तकाजा तो सब पर लागू होता है। आखिर राफेल सौदे को लेकर राहुल किस आधार पर प्रधानमंत्री को चोर कहने में लगे हुए हैं? पता नहीं वह इस तरह की राजनीति कब तक करते रहेंगे, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपना काम तेजी से करें। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यह आवश्यक है कि जिन मामलों की वह सुनवाई कर रहा है उनमें यह देखे कि उनका निपटारा तय समय में हो। यह ठीक है कि गत दिवस सारधा घोटाले में सीबीआइ की प्रगति रिपोर्ट देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो तथ्य उसके सामने रखे गए हैं वे बेहद गंभीर हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन इस सवाल का जवाब भी सामने आना चाहिए कि इस तरह के घोटालों की जांच कब तक होती रहेगी?

चुनौतियों का मौसम

उत्तराखंड में मौसम लगातार चुनौतियों में इजाफा कर रहा है। मार्च को महीना अंतिम चरण में है, लेकिन बारिश और बर्फबारी का क्रम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का बना रहेगा। लंबे समय बाद प्रदेश में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई और स्नो लाइन भी 1800 मीटर तक आ गई है। मौसम में इस कदर अनिश्चितता है कि पिछले दिनों उत्तरकाशी में पारा 30 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया, लेकिन सोमवार को बारिश और उच्च हिमालय में बर्फबारी के बाद यह फिर नीचे आ गया। यह सिर्फ उत्तरकाशी का ही नहीं, बल्कि पौड़ी, पिथौरागढ़ और चमोली का भी आलम है। भले ही यहां पारे ने ऐसी उछाल न ली हो, लेकिन मौसम की अनिश्चितता बरकरार है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव और चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण के तहत 11 अप्रैल को होना है। जाहिर है नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च के बाद प्रत्याशियों के सामने प्रचार के लिए बहुत कम समय शेष है। आलम यह है कि चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के कई क्षेत्र अब भी बर्फ से लकदक हैं। प्रत्याशियों के लिए इन इलाकों तक पहुंचना पहाड़ चढ़ने जैसा ही साबित होगा। बात यहीं तक सीमित नहीं है, मतदान की तैयारियों में जुटे आयोग के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर चार धाम यात्रा में भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सात मई को गंगोत्री-यमुनोत्री और नौ मई को केदारनाथ एवं दस मई को बदरीनाथ के कपाट खुलने हैं। आलम यह है कि केदारनाथ और बदरीनाथ में अब भी नौ से दस फीट बर्फ जमा है। गंगोत्री और यमुनोत्री की स्थिति भी ज्यादा अलग नहीं है। ऐसे में यात्रा से पहले व्यवस्थाएं सुचारु करना किसी चुनौती से कम नहीं है। सीमा सड़क संगठन को बर्फ हटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ में पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से पटा हुआ है। धाम में एक माह से बिजली नहीं है। बर्फबारी से लाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद इसे दुरुस्त नहीं किया जा सका। इसके अलावा वहां फ्रेब्रिकेटेड हट को भी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तिथि भी 25 मई से बढ़ाकर एक जून करनी पड़ी।

साफ नीयत से तय होगी देश की नियति

गिरीश्वर मिश्र

जनसेवा और अंत्योदय सबका नारा है, परंतु पूंजी के प्रति सबका कितना गहरा आकर्षण है, यह नेताओं की आय में अप्रत्याशित वृद्धि से लगाया जा सकता है

राजनीति एक सतत प्रवाह है जिसके अंतर्गत पहले जो कुछ हो चुका है उससे वर्तमान अछूता नहीं रहता और भविष्य की रचना में बीते अतीत को लेकर आधार सूत्रों की खोज की जाती है। आम चुनाव के मौके पर कांग्रेस और शेष गैर कांग्रेस दलों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खेमों में सत्ता की जोड़तोड़ में भाषा, आचरण और वैचारिक संगति-असंगति की चिंता से मुक्त होकर सारी मर्यादाएं तोड़कर जो दौड़धूप मचाई जा रही है वह सत्ता कब्जाने की हड़बड़ी ही दिखा रहा है। इस अफरातफरी का एकमात्र स्रोत मोदी-विरोध होता नजर आ रहा है। महागठबंधन किस तरह घोषित हुआ वह विचार और कार्यक्रम की साझी सोच के अभाव की स्वाभाविक परिणति है। पिछले आम चुनाव में कांग्रेस शासन के दस वर्षों में हुए तरह-तरह के अतिरेकों और संशयों के चलते कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। उच्चपदस्थ लोगों के आर्थिक भ्रष्टाचार में लीन होने के कारण सामाजिक जीवन में शुचिता और नैतिकता का एक महाशून्य उभरने लगा था। उस शून्य को भरने के लिए डरे सहमे लोगों ने, जिनके पास कुछ खास खोने को न था, एक बड़ा कदम उठाया था। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ जनता ने शासन की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपी थी। उनकी नवीनता, देश के प्रति उनका अनूठा जज्बा, दृढ़ता ने धूमिल और अस्त-व्यस्त हो रहे राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में नए रंग भरने की आशा बंधाई थी। उनकी मुखर संवाद शैली उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की घोर मितभाषिता के ठीक उलट जनता में सीधे पैठ बनाने वाली थी। शीर्ष पर पहुंचे राजनेता के व्यवहार और बातचीत में लोग स्वयं को ढूंढने और पाने लगे।

नरेंद्र मोदी का 'अच्छे दिन आएंगे' वाला जुमला लोगों के मन को को भा गया था। वे अपने-अपने ढंग से इसका इंतजार करते रहे और एक हद तक सरल और नोटबंदी जैसी कठिन हर पहल का साथ भी देते रहे। अब पांच साल बाद जब जनता जनार्दन से भेंट हो रही है तो वह सब लोगों को कचोट रहा है। ऐसे में मोदी को पुनर्स्थापित करने की मुहिम पहले जैसी आसान नहीं रही। मोदी सरकार की स्वाभाविक जवाबदेही बनती है कि वह अपना रिजल्ट कार्ड पेश करे। देश के सामने अनेक समस्याएं हैं जिन पर सबका ध्यान जाता है। कृषि, बाजार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, आवास, सड़क और अन्य अधोसंरचना का निर्माण, रोजगार और गरीबी, काले धन का संचय आदि की हकीकत से बखूबी वाकिफ मोदी ने ऐसे कई व्यापक सुधारों को अंजाम दिया जिनसे गरीबों, स्त्रियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों का भला हो सके। गरीबों को मिलने वाली सहायता के पैसे सीधे उन्हें ही मिलें और बिचौलियों से मुक्ति हुई। साथ ही देश की प्रगति और विकास के अनेक कार्य भी शुरू किए। इन मोर्चों पर उपलब्धि उतनी नहीं रही जितनी आशा की जाती थी। देश की अंतरराष्ट्रीय छवि में भी सुधार हुआ है।

समाज में कई श्रेणियां हैं। गरीब, अमीर, मध्यवर्ग, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अनुसूचित, दलित, बहुजन आदि सामाजिक और वैधानिक श्रेणियां हैं। इस प्रसंग में जाति का प्रश्न राजनीति की नब्ज बना हुआ है जिसे नकारना संभव नहीं दिखता। राजनीति में घोषित तौर पर सभी दल समाजवादी ढांचे को दिखाते हैं। समता, समानता और सबके लिए अवसरों की समान उपलब्धता को सैद्धांतिक रूप से तो सभी स्वीकारते हैं, पर व्यवहार में इसकी मुश्किलें सारे प्रयासों को निष्प्रभावी बन देती हैं। जनसेवा और अंत्योदय सबका नारा है, परंतु पूंजी के प्रति सबका कितना गहरा आकर्षण है, यह नेताओं की आय में अप्रत्याशित वृद्धि से लगाया जा सकता है।

अवधेश राजपूत

अब गणतंत्र के चुनावी उत्सव का माहौल गरमा रहा है। आरोपों-प्रत्यारोपों को इतिहास और पुरातत्व की खुदाई से निकल रहे ध्वंसावशेषों द्वारा पुष्ट करते हुए पेश किया जा रहा है। चमत्कृत कर सकने वाले करिश्माई खेल खेले जा रहे हैं। सभी दल और नेता एक बार फिर राजनीति के कुंभ में स्नान को आतुर हैं। मजमा लगाने की हर जुगत लगाई जा रही है। अब वे संत या साधु पुरुष तो रहे नहीं। उन्हें हर सुख-सुविधा, ऐशो-आराम की व्यवस्था करनी होती है। नारों के दम पर अक्षमता का दंभ लेकर भीड़ जुटाई जा रही है ताकि जनसमर्थन जुटाया जा सके। भाषा प्रयोग की छटाएं दिल दुखा रही हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की शब्द शक्तियां जिस तरह प्रयोग में आ रही हैं वह सुधी जनों के लिए दुख का एक बड़ा कारण हो रहा है। न भाषा की बंदिश, न उम्र या पद का ही कोई लिहाज। कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है। यदि विधानमंडल गणतंत्र के विद्यालय जैसे माने जाएं तो उसके विद्यार्थी भी आम विद्यार्थियों जैसे ही होते जा रहे हैं। सभा में वे प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। यदि आए तो हंगामा और निरर्थक प्रलाप ही उनका प्रिय शगल होता है। देश छोड़िए उन्हें अपने क्षेत्र के विकास की भी शायद ही चिंता हो। वे प्रश्न भी नहीं पूछते, न उपलब्ध विकास राशि का सदुपयोग ही कर पाते हैं। ऐसे में जनतंत्र का ढांचा यदि चरमराने लगे तो क्या आश्चर्य!

अपने हितों की पूर्ति के लिए आज राजनीति के सेनानी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के रथों की सवारी के लिए उतावले हैं। चुनावी समुद्र में अपना बेड़ा पार लगाने के लिए चाहे जैसे हो पनघट की टेढ़ी होती डगर तो पार करनी ही है। सत्ता-सुख मादक होता है और उस पर काबिज बने रहना या हथियाना ही परम धर्म है। वाद, प्रवाद, विचार, दुर्विचार सभी का स्वागत है। सारे वैचारिक या अन्य प्रकार के अंतर या बाह्य विरोध और आग्रह स्थगित कर वे समझौते के सभी प्रकार अपनाते हुए वोट-समीकरण को अपने पलड़े की ओर झुकाने को आमादा हैं। हद तो तब हुई जब एक दल को छोड़ दूसरे दल में जा रहे नेता के बारे में उनके पहले वाली पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि 'हमारे कहने पर और हमारी अनुमति से वह दूसरी पार्टी में गए हैं।' सत्ता कब्जाने का एकमात्र लक्ष्य सभी तरह के मतभेदों और आपसी कलह आदि पर भारी पड़ता है। परिणाम यह है कि स्थानीय स्वीकृति और राष्ट्र के स्तर पर किसी राजनीतिक पार्टी की छवि को एक साथ जुटाना मुश्किल हो रहा है। एक ही पार्टी अनेक राज्यों में अन्य पार्टियों के साथ किसी भी तरह के तालमेल के लिए स्वतंत्र हो रही है। कुछ दिनों तक तो गलबहियां अच्छी लगती हैं, पर जल्द ही मोहभंग हो जाता है।

आज विचारों की गली सूनी-सूनी सी है। वहां पसरे सन्नाटे में हर आवाज शोरनुमा लगती है। लोग लाचार हैं इनके कलरव और निनाद को झेलने के लिए। ऐसे में दृश्य मीडिया हर किसी जायज या नाजायज जरूरी या गैर जरूरी घटना को जरूरत से ज्यादा स्थान देता नजर आ रहा है। खबरों का टोटा पड़ा है। हर डीह डाबर की खबर ली जा रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रचार माध्यमों की सहायता से वोटरों के बीच हवा बनाने और फिर उनके मतों को बटोरने की सटीक तरकीबें ढूंढने में लग चुके हैं। पक्ष और सारी मर्यादाएं तोड़कर विपक्ष दिन-रात छिद्रान्वेषण करते हुए खामियों को निकालने में भरसक जुटा है। चुनाव देश की नियति निर्धारित करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि इसकी देख-रेख करने वालों की नीयत साफ और ईमानदार हो।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं)

response@jagran.com

बुजुर्ग नेताओं पर व्यर्थ का विलाप

राजीव सचान

जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव की महत्ता होती है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि राजनीति से रिटायर ही न हुआ जाए

गांधीनगर, गुजरात से लालकृष्ण आडवाणी के स्थान पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा के एक और पूर्व अध्यक्ष एवं बुजुर्ग नेता डॉ. मुरली मनोहर जोशी के बारे में यह स्पष्ट हो गया कि वह आम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। यह तब स्पष्ट हुआ जब डॉ. जोशी ने कानपुर के मतदाताओं को यह सूचित किया कि भाजपा महासचिव रामलाल ने उनसे कहा है कि उन्हें कानपुर या अन्यत्र कहीं से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यह खबर आते ही यह रुदन और तेज हो गया कि देखिए, भाजपा अपने बुजुर्ग नेताओं की किस तरह उपेक्षा कर रही है। इस रुदन में विरोधी दलों के नेताओं के साथ-साथ भाजपा को नापसंद करने वाले बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। उनमें आडवाणी और जोशी के प्रति अचानक जिस तरह सहानुभूति उमड़ पड़ी है उससे हैरानी ही हो रही है। भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों के जिन नेताओं को आडवाणी और जोशी को उम्मीदवार न बनाए जाने पर कथित तौर पर दुख है उनमें आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, ''जिन्होंने घर बनाया उन्हीं बुजुर्गों को घर से निकाल दिया? जो अपने बुजुर्गों का नहीं हो सकता वह किसका होगा? क्या यही भारतीय सभ्यता है? हिंदू संस्कृति तो यह नहीं कहती कि बुजुर्गों को बेइज्जत करो।'' यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनके बारे में हर कोई इससे अवगत है कि उन्होंने राजनीति में जाने और अपनी पार्टी खड़ी करने के बाद बुजुर्ग नेता अन्ना हजारे का कितना मान-सम्मान किया? निःसंदेह यह भी किसी से छिपा नहीं कि उन्होंने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं को एक तरह से धक्के देकर पार्टी से बाहर कर दिया था। ध्यान रहे कि प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी की स्थापना यानी घर बनाते समय एक करोड़ रुपये का चंदा दिया था।

शायद ही किसी को यह भ्रम हुआ हो कि अरविंद केजरीवाल इससे दुखी हैं कि भाजपा लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को चुनाव मैदान में नहीं उतार रही है। वह तो बस भाजपा पर कटाक्ष करने का बहाना तलाश रहे थे। वह उन्हें मिल गया और उन्होंने बिना समय गंवाए उसे भुना लिया। यही काम कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। यह बात और है कि सबको पता है कि कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव के निधन के बाद किस तरह उनका अपमान किया था। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर लाने की भी इजाजत नहीं दी गई थी और उलटे यह कहा गया था कि उनके शव को जितनी जल्दी हो हैदराबाद ले जाएं। आखिर अपने नेता की ऐसी घोर उपेक्षा करने वाले किस मुंह से लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को उम्मीदवार न बनाए जाने पर भाजपा को कोस रहे हैं? कांग्रेसी नेताओं को तो यह भी पता होगा कि उनके एक और बुजुर्ग नेता सीताराम केसरी किस तरह खूब अपमानित किए गए थे। नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी आडवाणी और जोशी की कथित अनदेखी पर यह फरमाया कि परिवार आधारित उनके जैसे दल अपने बुजुर्गों का कहीं अधिक सम्मान करते हैं। हालांकि सबने देखा है कि नेशनल कांफ्रेंस की तरह से परिवार आधारित समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह यादव का किस तरह सम्मान किया है?

कहना कठिन है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे या नहीं, लेकिन बेहतर होता कि भाजपा नेतृत्व उन्हें खुद सूचित करता कि वह किन कारणों से उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारना चाह रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनका आहत होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे भी बेहतर यह होता कि ये दोनों नेता खुद ही चुनाव न लड़ने की घोषणा कर देते और इसे लेकर संशय ही न पैदा होने देते कि उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा या नहीं? ऐसा इसलिए करना चाहिए था, क्योंकि एक तो भाजपा 75 साल से अधिक आयु के नेताओं को सक्रिय राजनीति से किनारे करने की अघोषित नीति पर अमल करती आ रही है और दूसरे, इन दोनों नेताओं की आयु ऐसी नहीं कि वे चुनावी राजनीति के लिए जरूरी भागदौड़ आसानी से कर सकें। लालकृष्ण आडवाणी 90 साल से अधिक के हैं तो मुरली मनोहर जोशी 85 के होने वाले हैं। क्या यह सही समय नहीं था कि ये दोनों नेता युवाओं को आगे आने और उन्हें मौका देने की अपील करते हुए स्वतः ही चुनाव न लड़ने की घोषणा कर देते? निःसंदेह राजनीति की तरह जीवन के हर क्षेत्र में अनुभव की महत्ता होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राजनीति से रिटायर होने के बारे में सोचा ही न जाए। अगर 80-90 साल के नेता चुनाव मैदान में उतरते रहेंगे तो फिर युवाओं को मौका कब मिलेगा? यदि भारतीय राजनीति में सक्रिय 50-55 साल की आयु के नेताओं को भी युवा नेता कह दिया जाता है तो इसका यह मतलब नहीं कि 85-90 साल की आयु वाले नेता चुनावी राजनीति से रिटायर होने का नाम न लें। यह हास्यास्पद है कि राजनीति में युवा चेहरों की कमी पर चिंता जताने वाले भी फिलहाल इस पर गम का इजहार करने में लगे हुए हैं कि भाजपा ने न तो लालकृष्ण आडवाणी को उम्मीदवार बनाया और न ही मुरली मनोहर जोशी को। अगर भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है तो फिर इसकी एक झलक चुनावी राजनीति में क्यों नहीं दिखनी चाहिए?

निःसंदेह यह कहना भी कठिन है कि भाजपा नेतृत्व ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को चुनाव मैदान में न उतारने का फैसला बुजुर्ग नेताओं को चुनावी राजनीति से दूर रखने की अपनी अघोषित नीति के तहत लिया या फिर वह इन दोनों नेताओं को चुनाव लड़ाना ही नहीं चाहता था। सच्चाई जो भी हो, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवार चयन की कोई स्पष्ट रीति-नीति नहीं बना रखी है। आखिर यह एक तथ्य है कि भाजपा ने आडवाणी और जोशी को तो चुनाव न लड़ाने का फैसला किया, लेकिन कई ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतार दिया जिनकी छवि ठीक नहीं मानी जाती। इनमें वह साक्षी महाराज भी हैं जो अपने उलटे-सीधे बयानों से पार्टी को न जाने कितने बार शर्मिंदा कर चुके हैं। लगता है नेताओं के चुनाव जीतने के साथ-साथ विद्रोह करके पार्टी का नुकसान करने की क्षमता का भी ध्यान रखा जाता है। भारतीय राजनीति में बदलाव बहुत मंथर गति से हो रहा है, लेकिन बुजुर्ग नेताओं से यह अपेक्षा करना गलत नहीं कि वे रिटायर होना सीखें।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संगति

सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को किसी न किसी के साथ की आवश्यकता जरूर होती है और यही संगति उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। संगति का प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से जहां व्यक्ति यश एवं कीर्ति कमाता है, वहीं बुरी संगति उसके पतन का कारण बनती है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता उसकी संगति से ही चल जाता है। किसी व्यक्ति का आचरण-व्यवहार जानना हो तो उसके मित्रों का आचरण जान लो। यानी जिस व्यक्ति के मित्र अच्छे आचरण वाले होंगे, वह वैसे ही आचरण को आत्मसात करेगा। इसी तरह जिस व्यक्ति के दोस्त दुष्ट एवं दुराचारी होंगे, वह निश्चित रूप से वैसा ही होगा।

कोई भी इंसान अपनी संगति से ही जाना-पहचाना जाता है। व्यक्ति पर संगति का असर जाने-अनजाने में पड़ ही जाता है। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को विवेक प्राप्त करने के लिए संगति को अपनाना चाहिए। यदि उसे अच्छे संस्कार और स्वच्छ परिवेश मिलता है तो वह कल्याण के मार्ग पर चलता है। यदि वह दूषित वातावरण में रहता है तो उसके कार्य भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को अपनी इच्छा-कामना को नियंत्रण में रखने के लिए अपनी संगति सुधारनी चाहिए। यदि मनुष्य अपनी संगति सुधार ले तो उसका जीवन सुधर जाएगा। संगति व्यक्ति को सदैव सद्कर्म एवं विकास के लिए प्रेरित करती और समाज में उच्च स्तर प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि संगति व्यक्ति को स्वाभिमानी और उसे कठिन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है।

मनुष्य को अपने मन में कामना-लालसा का बीज पनपने से पूर्व ही संतों एवं विद्वानों की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि जैसी उसकी संगति होगी, वह वैसा ही चिंतन करना शुरू कर देता है। संत कबीरदास कहते हैं कि यह तन मानो पक्षी हो गया है, मन इसे जहां चाहे उड़ा ले जाता है। जिसे जैसा संग मिलता है, संगति या कुसंगति, वह वैसा ही फल भोगता है। मतलब यह कि हमारा मन ही अच्छी या बुरी संगति में ले जाकर वैसे ही फल देता है। संगति का असर इस तरह होता है कि सज्जनों की संगति से दुर्जन भी सज्जन बन जाता है। यानी व्यक्ति योगी के साथ योगी और भोगी के साथ भोगी बन जाता है।

आचार्य अनिल वत्स

एक सराहनीय पहल

मताली जैन

ऊंची एड़ी वाली सैंडल्स पहनने से घुटनों और जोड़ों पर दबाव बढ़ जाता है जिससे महिलाओं में अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है

इन दिनों जापान में महिलाओं द्वारा एक ऑनलाइन अभियान कुटू की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत महिलाओं के लिए कार्यक्षेत्र में अनिवार्य हाई हील्स का विरोध किया जा रहा है। कुटू का जापानी भाषा में अर्थ जूता और दर्द है, इसलिए महिलाओं ने इस अभियान को भी कुटू नाम दिया है। दरअसल जापान में कामकाजी पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों के लिए कुछ ड्रेस कोड है। जहां महिलाओं को हाई हील्स पहनना अनिवार्य है तो पुरुषों को फॉर्मल ड्रेस के साथ क्लीनशेव में रहना पड़ता है। लेकिन अब महिलाएं इस ड्रेस का विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि हाई हील्स से उन्हें एड़ी में दर्द, कमर दर्द एवं अन्य कई तरह की परेशानियों से दो-चार होना पड़ता है। यह एक महिला विरोधी मानसिकता है और उन्हें हाई हील्स पहनने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

हाई हील्स महिलाओं के लिए मजबूरी एवं मर्जी, दोनों का ही सौदा है। जहां कुछ जगह हाई हील्स पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है तो वहीं अधिकतर महिलाएं फैशन की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होकर इसे पहनती हैं। इसे चाहे किसी भी रूप में पहना जाए, लेकिन यह सेहत और सौंदर्य, दोनों के लिए खतरनाक है। लगातार इसे पहनने से महिलाओं के शरीर की आकृति बिगड़ जाती है। इससे नितंब बाहर की ओर निकल जाते हैं और कमर चौड़ी हो जाती है। वहीं शरीर का पूरा वजन पंजों पर पड़ने के कारण टांगों की मांसपेशियां फूल जाती हैं और चाल बदल जाती है। आम तौर पर हाई हील्स पहनने एवं उसके विपरीत प्रभावों को लोग बेहद गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इसे लेकर महिलाओं को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। ऊंची एड़ी वाली सैंडल्स या जूतों से घुटनों और जोड़ों पर दबाव बढ़ जाता है। जिससे महिलाओं में अर्थराइटिस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और हड्डियों में टूट फूट होने लगती है।

हाई हील्स पहनने वाली महिलाओं को फ्लैट फुट की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से तलवों को सपोर्ट नहीं मिल पाता।

इस प्रकार यदि देखा जाए तो हाई हील्स न सिर्फ पैरों की नसों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसका असर पूरे शरीर पर देखा जाता है। इससे हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, साथ ही शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कमर, गर्दन आदि में दर्द होता है। इतना ही नहीं, अगर लंबे समय तक हाई हील्स को पहना जाए तो समस्याएं काफी घातक भी हो सकती हैं। हाल ही में जिस तरह जापान की महिलाओं ने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हाई हील्स की अनिवार्यता के विरुद्ध अभियान शुरू किया है, उससे प्रेरित होकर यकीनन पूरे विश्व में महिलाएं फैशन बनाम सेहत में से सेहत का ही चयन करेंगी। वास्तव में हाई हील्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, बस इसे सीमित समय के लिए पहना जाना चाहिए। साथ ही इसे पहनते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे हाई हील्स पहनने से पहले तलवों के नीचे सिलिकॉन के हील पैड का इस्तेमाल करें। साथ ही पतली हील के स्थान पर मोटी हील पहनें, यह पैरों को ज्यादा सपोर्ट देती है। वहीं अगर किसी महिला के लिए इसे पहनना असहज हो तो वह फैशन की दौड़ में पड़ने के बजाय अपने शरीर की सुने।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सबको रोजगार देना मुश्किल

रोजगार का सवाल कितना गंभीर शीर्षक से लिखे अपने लेख में बलबीर पुंज ने रोजगार जैसे जटिल मुद्दे को वर्तमान परिदृश्य से रूबरू कराने की कोशिश की है। किसी भी शासनकाल में यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारों ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। सरकारें भी क्या करें देश में बेरोजगार युवाओं की फौज इतनी अधिक है कि हर हाथ को रोजगार देना भी मुमकिन नहीं है। हर हाथ को रोजगार देने का मतलब है देश से गरीबी को जड़ से खत्म करना। ऐसा कर पाना दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था के बजट से अभी बाहर है। कांग्रेस द्वारा गरीबों को आर्थिक सहायता देने का वादा भी इस गरीबी का कोई स्थाई समाधान नहीं है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि ऐसी लोकलुभावन योजनाएं केवल देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने और देश के आवाम को आलसी बनाने का ही जरिया हैं। सोचने का विषय है कि जब बगैर कुछ किए ही खाते में पैसे की बरसात होगी तो काम करना कौन चाहेगा। जीत की आस में विपक्ष का यही आलम रहा तो बेरोजगारी और गरीबी का अंत कभी नहीं हो सकता, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को इससे चुनावी लाभ जरूर हो सकता है।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

उभरता हुआ समीकरण

देश के तमाम राजनीतिक दल एकजुट होकर लड़ने या गठबंधन करने के बजाय चुनावों के बाद बनने वाले समीकरणों के बाद ही उचित कदम उठाने की सोचते हैं। चुनावों के बाद सबको पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है और उसके बाद ही वे मोल-भाव तय करते हैं। क्षेत्रीय दलों का अपने-अपने राज्य में दबदबा होता है। वे अपना वजूद और दबदबा कायम रखना चाहते हैं और किसी अन्य बड़े या छोटे राजनीतिक दल को अपने इलाके में घुसपैठ नहीं करने देना चाहते। इसलिए बिहार जैसे राज्य में अपना जनाधार रखने वाले लालू प्रसाद ने कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट ही दीं। उप्र में सपा और बसपा ने खुद गठबंधन करके मृतप्राय अवस्था वाली कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया। गठबंधन का युग हम देख ही चुके हैं और उनके राजनीतिक परिणाम दुखद ही रहे हैं। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी इन छोटे-छोटे दलों से आज गठबंधन पर मजबूर है। अब देखना यह है कि एकला चलो रे की नीति पर चलने वाले क्षेत्रीय दल चुनावों के बाद क्या गुल खिलाते हैं।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

क्यों नहीं मिटी गरीबी

यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 1971 में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ, देश बचाओ का नारा देने के बाद भी आज तक गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सका। 1971 से शुरू हुआ सफर 2019 तक चलता ही जा रहा है, लेकिन गरीब आज भी दो जून की रोटी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी वोट के लिए गरीबी मिटाओ का नारा दे रहे हैं और गरीबों को 72 हजार प्रति वर्ष देने का प्रलोभन दे रहे हैं। यह सोचने वाली बात है कि इतने साल बीतने के बाद भी गरीबी भारत से नहीं मिट सकी। इसमें नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है जो नहीं चाहते हैं कि गरीबी हटे, क्योंकि अगर देश से पूर्णतया गरीबी हट जाएगी तो नेता कहां जाएंगे इसलिए राजनीति में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि गरीबी देश में रहे, क्योंकि इसी के नाम पर वोट मिलता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर इंदिरा गांधी वास्तविक रूप से गरीबी हटाने के प्रति कटिबद्ध होतीं तो गरीबी को हटाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने भावी पीढ़ी के लिए इस मुद्दे को छोड़ दिया। यही कारण है कि आज जनता को सत्ता प्राप्ति के लिए 72 हजार रुपये का शिगूफा दे राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देख रहे हैं।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

राजनीतिक बोध जरूरी

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा कि वे दल बदल करने वाले अवसरवादी नेताओं से नाखुश हैं। दल बदल करने के बजाय उन्हें अपनी विचारधाराओं पर प्रतिबद्ध रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेसिर पैर के बयानों के बीच यह बयान सुकून देने वाला वाला है। राजनीति में शुचिता की बातें सब करते हैं, लेकिन कथनी के साथ करनी में न्याय कोई नहीं करता। यही कारण है कि आज के दौर की राजनीति में गंदगी फैलने लगी है। राजनीति में हार-जीत, धूप-छांव चलते रहते हैं, लेकिन जिस दल का नमक खाया उसी दल के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता दिखाना ही असली राजनीतिक बोध है।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई- mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई